खाद्य एवम पोषण सुरक्षा समुदाय

Solution eXchange
Wider Choices Smarter Development

सोल्यूशन एक्सचेंज - खाद्य एवम पोषण सुरक्षा समुदाय एकीकृत उत्तर

सवाल : 'समुदाय चलित व प्रबंधित अन्न अधिकोषों का विकास – अनुभव

संकलन: गोपी घोष, रिसोर्स परसन, राज गांगुली, सलाहकार, और टी. एन. अनुराधा, शोध सहयोगी

प्रकाशन तिथी: 30 जून 2009

द्वारा उत्पल मैत्रा, एम.पी.आर.एल.पी, डी. एफ. आई. डी. एवम मध्यप्रदेश सरकार की परियोजना, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रेषित 4 मई 2009

मध्यप्रदेश ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (एम.पी.आर.एल.पी) (www.mprlp.in), मध्यप्रदेश के नौ आदिवासी बहुल जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना गरीबी से ग्रस्त परिवारों को गरीबी के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

'खाद्य सुरक्षा' के विभिन्न चुनौतियो को संबोधित करने के लिए एम.पी.आर.एल.पी परियोजना का एक कार्यक्षेत्र है -'अन्न अधिकोष'। अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि अन्न अधिकोषों का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी सफलता बहुत सारे कारणों पर निर्भर करती है जैसे प्रबंधन व्यवस्था, सदस्यों की भागीदारी, कार्यान्वन, इलाके में समुह गठन का इतिहास, खाद्यान्न स्रोतो एवम् भंडारण व्यवस्था आदि।

यह परियोजना इस तरह के विभिन्न 'समुदाय चालित व प्रबंधित' अन्न अधिकोषों के प्रयासो से निम्नलिखित विषयों पर परामर्श लेना चाहता है।

- अन्न अधिकोषों के प्रतिफल विशेषतः लागत प्रभाविता, गरीबी, लिंग एवम् सामाजिक समावेश आदि पर क्या प्रमाण उपलब्ध है ।

- समुदाय चालित एवं प्रबंधित अन्न अधिकोषों के सफल गठन व संचालन के क्या मानदंड कारक है, विशेषतः समुह गतिविधि, सामुदायिक संगठन, भागीदारी, प्रचालन, प्रबंधन, वाणिज्यिक / वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता आदि मुद्दों पर प्रकाश डालें ।
- इस तरह के सफल प्रयासों और मॉडलों पर सूचना और संपर्क की जानकारी दे ।

मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के चुनौतियों को संबोधित करने के मद्देनज़र अन्न अधिकोषों के विकास और विस्तार के लिए यह परियोजना सदस्यों के अमुल्य विचारों व अनुभवों से अधिक लाभान्वित होगा।

Responses were received, with thanks, from

1. राज गांगुली, एफ.ए.ओ, नई दिल्ली
2. मारुति उपारे, स्वतंत्र परामर्शदाता, मुंबई
3. किरन कुलकर्नी, आई. आर,सी.ई.डी., सांगली, महाराष्ट्र (प्रतिक्रिया 1 ; प्रतिक्रिया 2)
4. शंभू घटक, सी.एस.डी.एम.एस, नई दिल्ली
5. रामित बासु, यूनीसेफ, नयी दिल्ली
6. भवानी , एम.एस.एस.आर.एफ., चेन्नई (प्रतिक्रिया 1 ; प्रतिक्रिया 1)
7. के. वी. पीटर, विश्व नोनी अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
8. अंजली त्रिपाठी, केथोलिक रिलीफ सर्विजेस (सी.आर.एस), लखनऊ
9. निर्मला सुमन, यूनीसेफ, लखनऊ
10. नीरा रामाचन्द्रन, स्वतंत्र परामर्शदाता, नई दिल्ली
11. दिलनवाज़ महंनती, आई.एल.ओ, नई दिल्ली
12. राधा गोपालन, ऋषि वैली स्कूल, मदनपल्ली, चितुर, आन्ध्रप्रदेश
13. अल्का पांडे, द इंडियन एक्सप्रेस, लखनऊ
14. अरद्धेन्दू एस. चटर्जी, डी.आर.एस.सी., कोलकाता
15. अच्युत दास, अग्रगामी, काशीपूर, उड़ीसा
16. रूचिरा भट्मिश्रा, कोर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका
17. सूरेश पटेल, कर्मदक्ष, बिलासपूर

अन्य योगदान का स्वागत है।

प्रतिक्रियओं का सारांश

तुलनात्मक अनुभव

संबंधित संसाधन

पूर्ण प्रतिक्रियांए

प्रतिक्रियाओं का सारांश

अन्न अधिकोष स्थानीय समुदाय को सामुहिक रूप से अन्न संग्रह करने व जरूरत के समय पर उपयोग करने का एक अच्छा मौका प्रदान करता है। चर्चासत्र ने क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्न अधिकोष को एक माध्यम के तौर पर देखा, विभिन्न क्रियाशील मॉडलों की जानकारी दी और इसकी स्थिरता और निरंतरता के लिए सुझाव दिए, जिनमें समुदाय की भागीदारी सबसे मुख्य कारण बनके उभरा।

अन्न अधिकोष स्थानीय खाद्य असुरक्षा को हल करने में सहायक होता है विषेशकर फसल विहीन समय और प्राकृतिक आपदा के समय क्षणिक भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए। सदस्य अन्न अधिकोष में अनाज रखते है, जिसे वे ब्याज सहित वापस करते है। स्थानीय खाद्यान्न कमी की स्थिति में, समुदाय प्रबंधित अन्न अधिकोष केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते है।

फसल लगाने के समय बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अन्न अधिकोष, 'बीज अधिकोष' की तरह भी कार्य कर सकते है। इससे स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और पोषक तत्वों से भरपूर स्थानीय फसलों जैसे कि मिलेट्स और दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्षेत्र में मिलेट्स की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाईटी ने आन्ध्रप्रदेश में एक मिलेट कैम्पेन चलाया।

बुन्देलखंड क्षेत्र में, चने की विकसित प्रजाती और धान की अगेती किस्मों द्वारा किसानों को समर्थन दिया गया। बीज और अनाज अधिकोष की एकीकृत परिकल्पना किसानों को अगले फसल चक्र में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और उनके खाद्यान्न की जरूरतों को भी पूरा करता है। गुणसुत्र-बीज-अनाज की अवधारणा जैव संरक्षण, देशी फसलों तथा फसल चक्र को बढ़ावा देने एवम लंबे समय तक खाद्य सुरक्षा की निरंतरता को संबोधित करने में भी मदद कर सकते है।

गरीबी से त्रस्त समुदाय जो कि अक्सर महाजनों से उधार लेकर अपने खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करते है, उनके लिए अन्न अधिकोष ऋण सेवाएँ उपलब्ध कर एक मूल्यवान विकल्प सिद्ध होता है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त गाँवों में, अन्न अधिकोष ने गाँवों के समुदाय को देशी उपायों द्वारा, खाद्य सुरक्षा एवम ऋण के मुद्दों को संबोधित करने मे सक्षम किया है।

अन्न अधिकोष के क्रार्यकलापों एवम प्रबंधन में महिलाएँ केन्द्रीय भूमिका निभातें हैं। भूमिहीन दलित महिलाओं के लिए अन्न अधिकोष की एक परियोजना, सांगली नगर निगम की बस्तीयों मे जीवन स्तर को बढ़ाने में कामयाब रहा हैं। महिलाएँ वर्ष भर बीजों को बचाकर अन्न अधिकोष में जमा करती है। चुँकि महिलाओं का बाजार जाना कम हो पाता है अन्न अधिकोष उन्हें कृषि के लिए जरूरी बीज लेने में सहायता देता है।

अन्न अधिकोषों के लागत प्रभावशाली होने के काफी साक्ष्य है क्योंकि ये स्थानीय समुदायों के पहल पर ज्यादा निर्भर होते है और संस्थागत पहल पर कम। इस तरह के विकेन्द्रीकृत एवम समुदाय प्रबंधित अन्न अधिकोषों के प्रभावशाली होने के निम्न कारण है – माल ढलाई की लागत में कमी, कम नुकसान, स्थानीय अनाज सरंक्षण के तरीके, कम खरीद लागत आदि।

अन्न अधिकोषों के लंबे समय तक निरंतरता और स्थिरता के सफलता के मापदंड बहुत सारे है लेकिन सबसे मुख्य कारण है समुदाय की भागीदारी और उनका प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी होना। स्थानीय पंचायत समिति का मजबूद नेतृत्व और उनका समुदाय के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल भी अति आवश्यक है। समुदाय को भी जरूरत है कि वह अन्न अधिकोष के प्रबंधन से संबन्धित ज्ञान और कुशलताओं से परिचित हो। पहुँच में आसानी हो इसलिए गाँव में अन्न अधिकोष का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण है विषेशतः उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ का प्रकोप होता है।

उचित भंडारण का प्रावधान एक और मुख्य पहलू है, जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अयोग्य भंडारण के चलते बहुत सारा खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। अन्न अधिकोष के सफलता में अनाज की किस्म भी बहुत महत्बपूर्ण कारक है क्योंकि लेनदेन में उचित गुणवत्ता की स्थानीय किस्मों की माँग होती है।

स्थायीत्व के लिए, अन्न अधिकोष का समुदाय द्वारा स्वमित्व काफी महत्वपूर्ण है। साहेल क्षेत्र में, आई.एल.ओ. के एकोपाम प्रोग्राम ने अन्न अधिकोषों की स्थापना स्थापित, नियंत्रण एवम विस्तार के लिए, उचित स्थिति बनाई है। स्थानीय समुदायों की विशेषताएँ एवम उनकी जरूरतों तथा क्रियांवन के समय सभी पात्रों की भागीदारी सुनिश्चित के करने के कारण, इस दृष्टिकोण को काफी महत्व दिया गया है।

अन्न अधिकोष की निरंतरता एवम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक विकल्प हो सकता है, पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत 'अन्न कोष' के प्रावधान का लाभ लेना। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत के अगुआई मे स्वंय सहायता समुह भी अन्न अधिकोषों का प्रबंधन कर सकते है। 'अग्रगामी' ने उडीसा के आदिवासी इलाकों में सामुदायिक अन्न अधिकोषों को स्थापित किया है और उनका मॉडल फसल हीन समय मे भुखमरी और कुपोषण से निपटने में कारगर सिद्ध हुआ है। उडीसा में स्वंय सहायता समुह द्वारा प्रबंधित अन्न अधिकोषों के सफल उदाहरण मौजूद है, जो कि नाबार्ड द्वारा समर्थित है। छत्तीसगढ के बतरा पंचायत का अन्न अधिकोष कार्यक्रम ने कलस्टर

दृष्टिकोण अपनाया है। चर्चा में जिन अन्य अन्न अधिकोष मॉडल की जानकारी दी गई उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के ओराई जिले मे परमार्थ समाज सेवी संगठन द्वारा पचास अन्न अधिकोषों का सफल क्रियांवन शामिल है। पश्चिम बंगाल में डी.आर.सी.एस.सी. संस्था ने एक परिक्रामी कोष द्वारा (जो अन्न अधिकोषों को वस्तु के रूप में प्रारंभिक कोष मुहैया कराता है) बहुत सारे अन्न अधिकोषों को समर्थन दिया है। झारखंड और बिहार में खाद्य एवम आजीविका सुरक्षा योजना ने गाँवों के समूह के बीच अन्न अधिकोषों की स्थापना की है जिसमें अन्न अधिकोष निर्माण हेतु व्यवहार में न आनेवाले ढ़ाँचे का पुनरूद्धार किया गया।

भुखमरी एवम कुपोषण से लड़ने हेतु पारिवारिक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को मजबूत/सुदृढ़ करने के लिए जरूरत है - समुदाय, पंचायत, गैर सरकारी संस्था, सरकारी विभाग एवम संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के बीच एक सहयोगी रूपरेखा बनाई जाए। नरेगा जैसी राष्ट्रीय कार्यक्रम फसल की पैदावार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है जिससे कि पंचायत स्तर पर खाद्य भंडार बढ़ सके। पिछडे क्षेत्रों की अनुदान राशि (बी.आर.जी.एफ. फडं) के तहत, जरूरी संरचना बनाने के लिए आवश्यक राशि जुटाई जा सकती है।

अन्न अधिकोषों के सुचारू रूप से संचालन एवम प्रबंधन में कुछ चिंता जताई गई, जिनकों अगर पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए तो इन हस्तक्षेपों की लंबे समय तक निरंतरता एवम स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। बचत एवम ऋण के रूप में अनाज, एक जटिल प्रबंधन व्यवस्था है और कभी-कभी अपर्याप्त क्षमता के कारण स्वंय सहायता समुह या समुदाय इसे सही तरह से संभाल नही सकती।

निरंतर सूखे और बाढ़ से फसलों का नुकसान, फसलों की पैदावार में तेजी से गिरावट आदि अन्न अधिकोषों के विफलता का कारण बनते है और इसलिए इन इलाकों में सामुदायिक अन्न अधिकोषों की रूप रेखा बनाने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह आपातकाल में भंडार की पूनः पूर्ति हो। कुछ क्षेत्रों मे अन्न अधिकोषों का महत्व कम हुआ है, जिसके विभिन्न कारण है – सरकारी योजनाओं से चावल एवम गेहूँ की समुचित आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.), दैनिक मजदूरी कार्यों में वृद्धि जिससे बाजार से चावल खरीदने के लिए पैसे मिलना, अन्न अधिकोषों का प्रायः धान में लेनदेन, जबकि लोगों को अन्य खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता – दलहन. खाद्य, तेल, मसालें, कंद मूल आदि। इसलिए अन्न अधिकोषों का सावधानी पूर्वक भौगोलिक लक्ष्य निर्धारण, इसके स्थिरता एवम निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।

समय के साथ अन्न अधिकोषों का विकास एक सफल खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप से लेकर ग्रामीण समुदाय के आर्थिक एवम समाजिक विकास के लिए एक व्यापक स्वंय सहायता व्यवस्था के रूप मे हुआ है।

अन्न अधिकोष की सफलता एवम इसकी स्थिरता व निरंतरता के लिए सामरिक योजना और प्रभावी प्रबंधन जिसमें स्थानीय समुदाय शामिल हो, अति महत्वपूर्ण है।

तुलनात्मक अनुभव

उड़ीसा

वस्तु के रूप में बचत, थाउमुल रामपूर ब्लाक, जिला कालाहांडी (*द्वारा मारुति उपारे, स्वतंत्र परामर्शदाता, मुंबई)*
इस अन्न अधिकोष योजना ने वस्तु के रूप में बचत, इन बचतों के एवज में संसाधन जुटाना, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में भाग लेना और बीज मुहैया करने आदि, को सुनिश्चित किया। इसे 17 गाँवों मे क्रियांवन किया गया, जिसमें 50 एस.एच.जी. को बढ़ावा देना और 3 अन्न अधिकोषों की स्थापना सम्मिलित थी। नगद बचत के अलावा अनाज भंडारण के एवज में बचत का मुद्रीकरण कराया नबार्ड द्वारा एस.एच.जी को ऋण मुहैया करया गया। ठंतीस एस.एच.जी को बढ़ावा दिया गया और 963 किलों अनाज का बचत किया गया। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

समुदाय के द्वारा अपने अनाज का उत्तरदायित्व लेना (*द्वारा भवानी , एम.एस.एस.आर.एफ., चेन्नई, प्रतिक्रिया 1)*
'ग्राम विकास' 200 गाँवों मे अन्न अधिकोषों को समर्थन देता है। अन्न अधिकोषों का दैनंदिन प्रबंधन समुदाय सुनिश्चित करता है-कहाँ, किसे, कैसे भंडार करना है, जमा राशि कैसे लेना है, उधार व वापसी भुगतान के मानदंड आदि। फसल कटाई के समय में अनाज को जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरित की जाती है। वापसी भुगतान के कड़े मानदंड निर्धारित किए जाते है जिसे गाँव की समिती/महिला समिती पर्यवेक्षण करती है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

सामुदायिक फसल - सामुदायिक वरदान, काशीपूर (*द्वारा अच्युत दास, अग्रगामी, काशीपूर, उड़ीसा)*
राज्यभर में, अग्रगामी ने आदिवासी समुदाय को अन्न अधिकोष शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। इन अधिकोषों ने सबसे खराब खाधान्न कमी के समय, गाँववालों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है और उन्हे महाजनों के चुंगल से आजाद किया है। अग्रगामी के अन्न अधिकोष मॉडलों की काफी सराहना हुई है और इन्हें सरकारी एवम विकास संस्थाओं द्वारा प्रतिरूप के रूप में लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

महाराष्ट्र

अन्न अधिकोष जीवन के स्तर को बढ़ाता है**,** सांगली *(द्वारा किरन कुलकर्नी, आई. आर,सी.ई.डी., सांगली, महाराष्ट्र, प्रतिक्रिया 1)*

सांगली नगर निगम के बस्तीयों में भुमिहीन दलित महिलाओं के लिए अन्न अधिकोष योजना विगत 3 वर्षो से चल रही है। महिलाओं को पहले के 30 रूपया प्रतिदिन के अपेक्षा 50 रूपया प्रतिदिन दैनिक मजदूरी मिल रही है। उनके घर में हमेशा काफी खाद्य भंडार होता है। प्रत्येक वर्ष वे खुद बाजार जाते है और मुल्य निर्धारण कर अनाज खरीदती है। इन महिलाओं ने अब एक दुकान खोलने का निर्णय लिया है।

अन्न अधिकोष कुछ भिन्नताओं के साथ, अतापढ़ी तालूक, जिला सांगली (*द्वारा किरन कुलकर्नी, आई. आर,सी.ई.डी., सांगली, महाराष्ट्र, प्रतिक्रिया 2*)
माईक्रो फाईनेंस की अनाज के रूप में 'इनोवेशन फंड' मॉडल' ने अन्न अधिकोष की मॉडल आरंभ कर्ने में स हायता की है। गाँव के लोग सामुदायिक अन्न अधिकोष से, अनाज उधार लेते है और फसल कटाई के बाद 25% ब्याज सहित अधिकोष को वापस कर देते है। अन्य जरूरतमंद गाँवों में अन्न अधिकोष शुरू करने के लिए, प्रारंभिक पूंजी के तौर पर इस ब्याज को एक परिक्रामी कोष की तरह व्यवहार किया जाता है। चार वर्षो के सफलतापूर्वक ब्याज वापसी (25% वार्षिक) के बाद गाँववालों का 100% ऋण चुकाना हो जाता है। और साथ ही अन्न अधिकोषों मे उनके हिस्से का अनाज भी मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

द्वारा शंभू घटक, *सी.एस.डी.एम.एस, नई दिल्ली*

छत्तीसगढ़

राम कोठी - अन्न अधिकोष, तेलीगोन्द्रा गाँव
आज सूखे और कम फसल उत्पादन से सामना होने के समय यह अधिकोष गाँववालों के लिए कोई वरदान से कम नही है। राम कोठी एक अन्न अधिकोष के रूप में, 44 वर्ष पहले, एक त्योहार के दौरान जमा किए गए दान और अतिरिक्त फसल उत्पादन से, शुरू की गई थी। अतिरिक्त अनाज को बेचकर गाँव ने एक स्कूल भी शुरू की है। अधिकोष द्वारा चलित विभिन्न योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति भी गठित की गई है। पहले वे केवल खाद्यान्न देते थे लेकिन अब वे पैसे भी उधार देते है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत सारा उत्पाद भंडार में है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

अन्न अधिकोष खाद्य असुरक्षा को संबोधित करता है, करजत ब्लाक, जिला रायगढ़
खाद्य असुरक्षा आदिवासी परिवारों में काफी गंभीर थी, जिससे भुखमरी और कुपोषण के कारण मौत तक होती थी। 1987 से 2005 के बीच, ए.डी.एस. ने इस समस्या के निराकरण के लिए 150 ग्रामीण अन्न अधिकोष की स्थापना की और धान की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस योजना की सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी आदीवासी क्षेत्रों में अन्न अधिकोष की स्थापना की। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

अन्न अधिकोष के लिए कलस्टर एप्रोच, बतरा ग्राम पंचायत् (*द्वारा सूरेश पटेल, कर्मदक्ष, बिलासपूर*

केन्द्रीय सरकार ने गाँव के इस अन्न अधिकोष परियोजना को समर्थन दिया है। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए है। कर्मदक्ष ने इसके कार्य को सशक्त करने के लिए कलस्टर एप्रोच द्वारा सहायता दी है। यह अन्न अधिकोष 195 महिलाओं द्वारा जो कि 13 समुह में संगठित थी, 40 क्विंटल चावल द्वारा शुरू की गई थी। अब इससे 16 समुहों की 227 महिलाएँ, फायदा ले रही है।

झारखंड और बिहार

अन्न अधिकोषों की निरंतरता और स्थिरता के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक *(द्वारा रामित बासु, यूनीसेफ, नयी दिल्ली)*
जीन कैम्पेन द्वारा क्रियांवित खाद्य एवम आजीविका सुरक्षा योजना का एक मुख्य गतिविधि था - गाँव के समुहों के बीच अन्न अधिकोष स्थापित करना। यह योजना एक समुदाय स्वामित्व रूपी पहल था जिसमें गाँव ने व्यवहार न आनेवाले एक संरचना का नवीकरण कर अधिकोष स्थापना करने का निर्णय लिया। इसमें जरूरत की उपकरणे जिनका मुल्य कुल 70,000 रूपया था मुहैया कराई गई। लेकिन इस पहल के स्थायीत्व मे कुछ मुद्दे है।

द्वारा भवानी, एम.एस.एस.आर.एफ., चेन्नई प्रतिक्रिया 1

आन्ध्रप्रदेश

अन्न अधिकोष का व्यापार मॉडल
एक समुदाय प्रबंधित अन्न अधिकोष जिसमें महिलाएँ शामिल है 'चावल ऋण रेखा' के आधार पर एक व्यापार मॉडल विकसित किया है। उन्होनें परिवार का चुनाव, अनाज जमा एवम वितरण् करने, किस्त जमा करने आदि के प्रक्रियाओं का निर्णय स्वंय किया है। सरकारी सहयोग से प्रत्येक महीना चावल ऋण के रूप मे दिया गया और सदस्यगणों ने ऋण में लिए गए चावल का भुगतान, नगद वापसी कर किया। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

अन्न अधिकोष बाजार की अपेक्षा कम मुल्य पर अनाज मुहैया कराती है, जिला मेडक
डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने 75 गाँवों की दलित महिलाओं को महिला सघंम बनाने में मदद की - जो फसल चुनाव का निर्णय लेती है और अन्न अधिकोष स्थापित करती है। ये अन्न अधिकोष अतिरिक्त फसल उत्पादन को जमा करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन सदस्यों को जिनके पास भुमि नहीं है, या जरूरत के मुताबिक फसल उत्पादन नहीं कर पाई है उनकों बाजार से कम मूल्य पर बेच देती है। अन्न अधिकोष उस अनाज को जो बीज के रूप में उपयुक्त न हो, उसे खुले बाजार में बेच देता है और पैसे को बैंक में जमा करता है अधिक जानकारी के लिए पढ़े

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश

अन्न अधिकोष हाशिए पर रहने वालों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, बुंदेलखंड *(द्वारा अल्का पांडे, द इंडियन एक्सप्रेस, लखनऊ)*
परमार्थ ने अन्न अधिकोषों की स्थापना की है जो समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रबंधित और शासित है। भाग लेने वाले समुदाय सदस्य, अपने सलाना उत्पादन का 20-25 प्रतिशत अनाज, अन्न अधिकोष में जमा करते है और फसल हीन समय में अनाज लेते है। वर्तमान समय में 43 अन्न अधिकोष कार्यशील है और 2-3 महीनों के खाध संकट समय के दौरान 645 लोगों के जरूरतों को पूरा करता है। इस सफलता के बाद, अन्न अधिकोषों का वृहत पैमाने पर विस्तार के लिए परमार्थ ने सरकार के साथ वकालत शुरू की है। अधिक जानकारी के लिए पढे

नई फसल चक्र व्यवस्था अन्न अधिकोषों को मदद करता है, बुंदेलखंड (*द्वारा अंजली त्रिपाठी, केथोलिक रिलीफ सर्विजेस (सी.आर.एस), लखनऊ)*
अगेती धान और चने पर आधारित एक नई फसल चक्र व्यवस्था, जिसमें कम सिंचाई लगता है और चने का अच्छा मूल्य भी मिलता है, काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है। इस योजना में बीज बैंक और अनाज बैंक की परिकल्पना समुदाय को बताई गई। इससे किसानों को अगामी फसल चक्र के लिए बीज प्राप्त करने में सहायता हुई और सुखे के समय अन्न अधिकोष से खाधान्न की जरूरतें भी पूरी हुई। अधिक जानकारी के लिए पढे

पश्चिम बंगाल

अन्न अधिकोष समुदाय को सशक्त करता है *(द्वारा अरद्धेन्दू एस. चटर्जी, डी.आर.एस.सी., कोलकाता)*
डी.आर.सी.एस.सी. ने बहुत सारे अन्न अधिकोषों को एक परिक्रामी निधि द्वारा समर्थन दिया है। समुदाय को अन्न भंडार के आधार में पत्थर या कंक्रीट स्लेब लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे चुहों द्वारा नुकसान न हो। यह पाया गया कि थोड़ा प्रशिक्षण और सामयिक परामर्श से, समुदाय अपना अन्न अधिकोष चला सकता है, प्रारंभिक कर्ज चुका सकता है और बहुत सारा पैसा व अनाज भी बचा सकता है। अधिक जानकारी के लिए पढे

मध्यप्रदेश

अन्न अधिकोष खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिला बेतुल (*द्वारा टी.एन.अनुराधा, शोध सहायक*)
30 गाँव में, 700 परिवारों के लिए महिला किसान एवम युवाओं के स्वंय सहायता समूह, गाँवों के किसानों से अनाज खरीदते है और उसमें से इतना बेच देते है जितने से लागत निकल आए और बाकी को बीज एवम अनाज अधिकोष में जमा करते है। अनाज और बीज उन लोगों को उधार में दिया जाता है, जिन्हें उसकी जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए पढे

अंतराष्ट्रीय

पश्चिम अफ्रीका

सामुदायिक अन्न अधिकोष - अकाल में एक वरदान, बुरकिनाफासो (*द्वारा [नीरा रामाचन्द्रन](), स्वतंत्र परामर्शदाता, नई दिल्ली)*
यह क्षेत्र प्रायः गंभीर खाधान्न की कमी से झूझता है। 1980 के दशक से, जब वर्षों तक सूखा पड़ा था, सामुदायिक अन्न अधिकोष खाधान्न कमी की स्थिति में गाँव आधारित समाधान देने के लिए, पूरे देश भर में काफी लोकप्रिय हो चुका है। वर्ष के सबसे अधिक संकटकालीन स्थिति में अन्न अधिकोष नियंत्रित मूल्य पर खाधान्न उपलब्ध कराता है। ओ.डी.ई. ने 100 से अधिक अन्न अधिकोष की स्थापना में समर्थन दिया है। ऊँचे दामों पर अनाज बेचकर अब ये बाजार को भी नियंत्रित करते है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

अन्न अधिकोष का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन, साहेल क्षेत्र *(द्वारा राज गांगुली, एफ.ए.ओ, नई दिल्ली और दिलनवाज महंती, आई.एल.ओ, नई दिल्ली)*
आई.एल.ओ. के एकोपाम परियोजना ने अन्न अधिकोषों के स्थापना, नियंत्रण एवम विस्तार के लिए उपयुक्त स्थिति बनाई है। इसने सहकारी संस्थाओं को जो कि सदस्यों द्वारा अपनी जरूरत के आधार पर प्रबंधित थी, को सशक्त किया है। इसने स्थानीय समुदाय की प्रकृति और जरूरतों को, तथा क्रियांवन के सभी चरणों में सभी पात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने को काफी महत्व दिया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े

संबंधित संसाधन

Recommended Documentation

Evaluation of ACOPAM Programme (*from Raj Ganguly, FAO, New Delhi and Dilnawaz Mahanti, International Labour Organization (ILO), New Delhi)*
Evaluation Report; International Labour Organization (ILO); Ministry of Foreign Affairs; 2002
Available at http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/Reports-programmes-of-action-and-plans/Reports/2003/Annual-Report-2002---Evaluation-activities-of-the-Norwegian-Ministry-of-Foreign-Affairs/5.html?id=420289

Programme includes cereal banks as a decentralised system of food security organized and managed by farmers at local level

Grain Banks Provide Food Security in Betul (*from T N Anuradha, Research Associate)*
Article; Poorest Area Civil Society Programme (PACS)
Available at http://www.empowerpoor.com/statestoriesdetail.asp?report=627&state=Madhya%20Pradesh

Mentions that many PACS Programme partners have brought in greater food security and helped break the vicious debt cycle by creating village grain banks.

Scheme for Assistance to Voluntary Agencies in Establishment of Grain Banks in Tribal Villages (*from Kiran Kulkarni, Institute of Rural Credit and Entrepreneurship Development (I.R.C.E.D.), Sangli, Maharastra, response 1)*
Proposal; IRCED; Submitted to Government of Maharastra

Available at http://www.solutionexchange-un.net.in/food/cr/res04050904.doc (Document Size: 58 KB)

Aims to solve indebtedness problem of tribal in Maharashtra and build their capacity through credit and savings programs for establishment of Grain Banks

From Shambhu Ghatak, Centre for Science, Development and Media Studies (CSDMS), New Delhi

Assessing and Supporting the Evolution of Grain Banks as Part of Food Sovereignty
Report; by Manjusha Khedkar; Academy of Development Science
Available at http://www.sas2.net/documents/Proceedings/Manjusha.pdf (PDF Size: 1.08 MB)

Suggest that the influence of Grain Banks must go beyond food security to include many other development activities of the village.

Chhattisgarh Grain Bank Ensures Food Security
Article; NDTV; Infochange; January 2003
Available at http://infochangeindia.org/200303052404/Poverty/News/Chhattisgarh-grain-bank-ensures-food-security.html

Reports the bank distributes grain to the poor as and when they need it and all the farmers benefit irrespective of their stature.

From Bhavani, MSSRF, Chennai

Transforming the Lives of Tribals
Article; by Author's title. Joe Madiath and R.V. Jaya Padma; Gram Vikas
Available at http://www.gramvikas.org/PDF/published/Transforming%20Tribals%20Lives.pdf (PDF Size:80 KB)

Mentions the importance of grain banks that plays a catalytic role in elevating tribal communities from subsistence level of existence and gives confidence to aspire for better

Addressing Drought in Hunger Areas - Towards a Grain Bank on AP
Report; by K S Gopal; Centre for Environment Concerns; Hyderabad
Available at http://www.cphp.uk.com/uploads/disseminations/R7828%20005%20Addressing%20Hunger%20in%20Drought%20Areas.pdf (PDF Size: 1.5 MB)

Reports on the innovative business model developed for grain banks managed by women under the Rice Credit Line Scheme

Good food, Indian-style
Article; by Keya Acharya; India Together; 19 March 2009
Available at http://www.indiatogether.org/2009/mar/agr-ddsfood.htm

Narrates the success of adopting indigenous knowledge of agriculture and the way women have managed to manage and sustain the operations of a grain bank

Poverty Eradication through Community Grain Banks (*from Kiran Kulkarni, Institute of Rural Credit and Entrepreneurship Development (I.R.C.E.D.), Sangli, Maharastra, response 2*)
Article; by Author's title. Name; Kiran Kulkarni; Institute of Rural Credit and Entrepreneurship Development (I.R.C.E.D.); Sangli
Available at http://www.solutionexchange-un.net.in/food/cr/res04050902.doc (Document Size: 80 KB)

Shares the demonstrated experience of poverty eradication at village level by implementing Grain Bank Programme

Double Cropping Rice-fallow Systems of South Asia (*from Anjali Tripathy, Catholic Relief Services, Lucknow)*
Project Details; Centre for Arid Zones Studies (CAZS-NR); Research in Use
Available at http://www.researchintouse.com/nrk/RIUinfo/PF/PSP35.htm

A new cropping system helps farmers grow two crops a year and the surplus is stored in Grain Banks managed by self help groups

From Nira Ramachandran, Independent Consultant, New Delhi

Community Grain Banks
Article; by Pasteur Samuel Yameogo; Tearfund International Learning Zone; West Africa
Available at http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+31-40/Footsteps+32/Community+Grain+Banks.htm

Demonstrates community grain bank are a solution to food security that helped the communities survive shortage during three rainy months of the year

Details of Low Cost Grain Storage Bins being used in India
Note; Food and Agriculture Organization of the United Nations
Available at http://www.fao.org/wairdocs/x5002e/X5002e02.htm

Provides details of various grain storage structure design and its construction that play a vital role in reducing or increasing the losses during storage

Recommended Organizations and Programmes

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Mumbai*(from Maroti Upare, Independent Consultant, New Delhi)*
2nd Floor, 'D' Wing, C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, Maharastra 400051; Tel: 91-22-26525068; Fax: 91-22-26530050 contact@nabard.org; http://www.nabard.org/microfinance/mf_projects.asp

Provides support in the predominantly tribal areas for construction and establishment of grain banks involving SHGs

From Shambhu Ghatak, Centre for Science, Development and Media Studies (CSDMS), New Delhi

Navdanya, New Delhi
A-60 Hauz Khas, New Delhi–110016; Tel: 91-11-26532124, 26968077; navslow@yahoo.co.in http://www.navdanya.org/news/4dec07.htm

Runs seed banks in various parts of the Country, the seed reproduces and multiplies. Farmers use seed both as a grain as well as for the next year's crop.

Gene Campaign, New Delhi
J-235/A, Lane W-15C, Sainik Farms, New Delhi-110062; Tel: 91-11-29556248; Fax: 91-11-29555961; mail@genecampaign.org; http://www.genecampaign.org/Sub%20pages/wws-ID4.htm

Works on germplasm conservation through the setting up of Gene-Seed Banks for the multiplication of traditional varieties to develop viable seed source for farmers

Agragamee, Kashipur*(from Bhavani, MSSRF, Chennai and Dilnawaz Mahanti, International Labour Organization (ILO), New Delhi)*
At/P.O-Kashipur, Dist.-Rayagada, Orissa-765015; Tel: 91-6865-285174; Fax: 91-6865-285174 info@agragamee.org; http://www.agragamee.org/foodsecurity_mgmt.htm

Helped establish grain banks in 700 villages, with the wholehearted support from the community, of which grain banks in 500 villages are functioning successfully

From Bhavani, MSSRF, Chennai

Antodaya, Kalahandi District
At/PO: Kaniguma, via: Bhawanipatna, Kalahandi District, Orissa-766001; Tel: 91-6670-32038, 34012; Fax: 91-6670-32038; antodaya_kld@hotmail.com; http://www.interconnection.org/antodaya/economic.html

Has promoted village level organizations (VLOs) to manage Grain Banks in the village

Gram Vikas, Ganjam
Mohuda Village, Berhampur, Ganjam, Orissa-760002; Tel: 91-680-2261866 to 2261869 ; Fax: 91-680-2261862 gramvikas@gmail.com; http://www.gramvikas.org/

Has supported in establishment of grain banks in over 200 villages in Orissa and empowered community towards its management and operation

Deccan Development Society (DDS), Hyderabad
101, Kishan Residency, 1-11-242/1, Street No. 5, Shyamlal Buildings Area, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016; Tel: 91-40-27764577, 91-40-27764744; Fax: 91-40-27764722 ddshyderabad@gmail.com; http://www.ddsindia.com/www/default.asp

Runs Community Grain Fund programme to rejuvenate marginalised lands in villages and through this offers a new coarse grain based PDS which is community -managed

M S Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai
3rd Cross Street, Institutional Area, Taramani, Chennai, Tamilnadu-600113; Tel: 91-44-22542698, 22541229; Fax: 91-44-22541319 hmrc@mssrf.res.in; http://www.mssrf.org/fs/index.htm

Apart from the extensive work on setting up grain banks, has developed a training manual on setting up Community Gene-Seed-Grain Banks based on pilot projects

Parmarth Samaj Sevi Sansthan, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh*(from Alka Pande, The Indian Express, Lucknow)*
Mona House, Churkhi Road, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh-285001; Tel: 91-5162-258412; Fax: Fax No. info@parmarth.org.in; http://www.parmarthindia.org/addressing/right_food.html; Contact Dr. Anil Singh. Director; Tel: 91-9415064472; parmarthorai@sancharnet.in

Works towards addressing food insecurity of the poor and marginalised communities through formation and strengthening of grain banks

Development Research Communication and Services Centre (DRCSC), Kolkata *(from Ardhendu S Chatterjee)*
58A, Dharmotola Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata 700042, West Bengal; Tel: 91-33-2442731, 24411646; Fax: 91-033 2442 7563; drcsc@alliancekolkata.com; http://www.drcsc.org/projects.html

Has supported establishment of many grain banks through a revolving fund that provides initial counterpart fund (in kind) to grain bank

Recommended Portals and Information Bases

(from Ardhendu S Chatterjee, Development Research Communication and Services Centre (DRCSC), Kolkata)

Backward Regions Grant Fund (BRGF), Ministry of Panchayati Raj http://www.brgf.gov.in/

Provides programme design details implemented by Panchayati Raj Institutions from planning to implementation, considers food and nutrition security aspects.

National Rural Employment Guarantee Act 2005, Ministry of Rural Development http://www.nrega.nic.in/

Provides livelihoods security for households in rural areas of the country, suggested as an avenue for augmenting grain banks for improved food security

Related Consolidated Replies

Designing of Grain Banks for Enhanced Food Security, from Sejal Dand, Anandi, Gujarat (Examples; Experiences). Food and Nutrition Security Community,
Issued 4 January 2006. Available at http://www.solutionexchange-un.net.in/food/cr/cr-se-food-04010601.pdf (PDF,Size: 120 KB)

Practical examples for designing community-managed grain banks, including a variety of models and approaches.

पूर्ण प्रतिक्रियांए

राज गांगुली, एफ.ए.ओ, नई दिल्ली

समय के साथ-साथ अन्न कोषों का विकास, खाद्द सुरक्षा के एक साधारण विकल्प से लेकर, ग्रामीण इलाकों के आर्थिक एवम सामाजिक विकास में एक स्वयं सहायता रूपी कार्यतंत्र के रूप में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न कोष, एक सामुदायिक गतिविधि के रूप में टिकाऊ व्यवस्था बन सकता है, अगर कुछ पहलूओं का ध्यान रखा जाए। प्रथमतः संलग्न लोगों को इसे अपना समझना पड़ेगा। उसके बाद किसी कुशल संगठन द्वारा सदस्यो का प्रशिक्षण कराना पड़ेगा। इनमें पारदर्शी प्रबंधन का विशेष उल्लेख होना चाहिए। इन सभी पहलूओं को पूरा करने से पहले, लोगों को अन्न कोषों के सफल निष्पादन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से अवगत कराना पड़ेगा।

एकोपाम कार्यक्रम (स्थानीय विकास के पहल में संगठनात्मक और सहयोगी समर्थन रूपी आई. एल. ओ. का एक कार्यक्रम) एक तकनीकी सहयोगी कार्यक्रम था जो कि पूरे साहेल क्षेत्रों में, अन्न कोषों के स्थापना, नियंत्रण और विस्तार के लिए स्थिती पैदा करने की कोशिश की थी। एकोपाम कार्यक्रम का उद्देश्य था सहकारी संगठनों को मजबूत करना व बढ़ावा देना, जो कि अपनें जरूरत के आधार पर सदस्यों द्वारा प्रबंधित थे।

एकोपाम कार्यक्रम का दृष्टिकोण स्थानीय समुदाय के विषेशताओं और जरूरतों पर ज्यादा महत्व देना था, विषेशतः यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्यों की भागीदारी हो। कार्यान्वन के सभी चरणों में, यह दृष्टिकोण स्थानीय स्तर पर परीक्षण करके, और समयानुसार धीरे से दृष्टिकोण में बदलाव लाने, उपकरणों का निर्माण और सलाह देने आदि पर निर्भर था ताकि अनुभवों को बाँटा जा सके वहाँ जहाँ कि परिस्थितीयाँ सामान हों।

इन कार्यक्रमों का विशेष योगदान था लाभार्थी संगठनों के नेतृत्व ओर इनके सदस्यों का, प्रबंधन के तरीके और भागीदारी विकास में प्रशिक्षण।

पन्द्रह वर्षो के एकोपाम परीक्षण प्रयासों के आधार पर विकसित प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मैन्युल (http://www.ilo.org/dyn/empent/docs/F1734331776/grain%20banks%20text.pdf) अन्न कोषों को चलाने के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सफल शिक्षण माध्यम है।

मारुति उपारे, स्वतंत्र परामर्शदाता, मुंबई
अन्न अधिकोष एक सामुदायिक गतिविधि है। उड़ीसा में, स्वयं सहायता समूहों द्वारा अन्न अधिकोष प्रबंधन के सफल प्रयासों के उदाहरण नाबार्ड द्वारा उल्लेखित है (http://www.nabard.org/microfinance/mf_projects.asp)। जिन्हें अनाज की आवश्यकता है वे सदस्य अन्न कोषों से अनाज लेते है और बाद में दोगूना अनाज वापस करते है जिससे कि भंडार की स्थिती बनी रहती है। यह बहुत लागत प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह के गतिविधियों का प्रयास मध्यप्रदेश में होना चाहिए।

किरन कुलकर्नी, आई. आर,सी.ई.डी., सांगली, महाराष्ट्र *(प्रतिक्रिया 1)*
आदिवासीयों और समरुप समुदायों के लिए अन्न अधिकोष एक बहुत बढिया योजना है। आबादी में भिन्नता होने पर हमें जरुरत के हिसाब से संरचना में बदलाव लाना होगा। मैं इस संबध में महाराष्ट्रा का अनुभव प्रस्तुत है http://www.solutionexchange-un.net.in/food/cr/res04050902.doc ।

किरन कुलकर्नी, आई. आर,सी.ई.डी., सांगली, महाराष्ट्र *(प्रतिक्रिया 2)*
महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत यह प्रस्ताव जिसको आधारित कर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ‘अनाज बैंक परियोजना’ को क्रियांवित करने के लिए ‘सरकारी संकल्प’ (गर्वमेंट रेसोल्यूशन) पारित किया गया था इस लिंक (http://www.solutionexchange-un.net.in/food/cr/res04050904.doc) पर उपलब्ध है । यदि मध्यप्रदेश का कोई विभाग इस प्रस्ताव को चाहता है तो वह इसे व्यवहार कर सकता है। जरुरत पडने पर एक नया प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

शहरी क्षेत्र में अन्न अधिकोष

विगत तीन वर्षों से हम लोग सांगली नगर निगम के बस्तीयों में रहने वाले दलित महिलाओं के लिए अन्न अधिकोष योजना चला रहे है। यह योजना काफी सफल रही है। यह लोग अब पहले के 30 रुपया प्रतिदिन की जगह पर 50 रुपया प्रतिदिन दैनिक मजदूरी प्राप्त कर पा रहे है। उनके नशाकोर पुरुष साथी अब पैसे के लिए मारपीट नही करते। उनके घर में अब काफी अनाज भरा-पड़ा रहता है जिसे उनके पति नहीं बेच पाते है। प्रत्येक वर्ष वे खुद बाजार जाते हैं और अनाज का मुल्य तय करके अच्छी खरीदारी करते हैं। इस साल इन महिलाओं ने खुद का अपना दुकान खोलने का निर्णय लिया है।

शंभू घटक, सी.एस.डी.एम.एस, नई दिल्ली

अन्न अधिकोष आदिवासी क्षेत्रों के गावों में रहने वाले समुदायों के लिए आपातकालीन स्थिति (सूखा, अकाल आदि) के दौरान, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मददगार साबित हो सकता है विषेशतः जब कि सरकारी, गैर सरकारी, अंतराष्ट्रीय या दाता एजेंसियों से तत्काल सहायता आने में देर हो रही हो।

अन्न अधिकोष महिलाओं के लिए भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है, जो अकसर सूखे और अकाल के दौरान उपेक्षित हो जाते है। महिलाएँ, सालभर अनाज इक्ठठा करने और अन्न अधिकोष में योगदान करके एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। चूकि महिलाए, आम संपति संसाधनों पर ज्यादा निर्भर करती है, और उनका बाजार जाना संभव नही हो पाता, इसलिए वे अन्न अधिकोषों के जरिए बचाए गए बीज को बुवाई के काम में ला सकती है।

अन्न अधिकोष ‘बीज कोष’ और गुणसुत्र बैंक (जीन बैंक) के रुप में भी कार्य कर सकता है। बचाए गए अनाज को आगामी मौसमों में बुवाई के लिए इस्तमाल किया जा सकता है। अक्सर हम बहुराष्ट्रीय कंपनिओं और बीज कंपनिओं द्वारा गुणसुत्रों की चोरी के बारे में सुनते है। पारंपरिक और स्थानीय किस्मों के बीजों को जिनके अपने अद्वितीय गुण है, अन्न अधिकोषों के जरिए सहेजे जा सकते है।

अन्न अधिकोष, स्थानीय महाजनों द्वारा ऋण आवटन के दोषों को भी कम कर सकता है, जहाँ पर ब्याज की दर काफी ज्यादा होती है। खपत के लिए उधार की आवश्यकता काफी कम हो सकती है, यदि ज्यादा से ज्यादा अन्न अधिकोष की स्थापना हो।

लागत प्रभावशीलता

अन्न अधिकोष लागत प्रभावी हो सकते है, क्यों कि यह स्थानीय पहल पर निर्भर होते है, और संस्थागत पहल पर कम, और इसके बहुत सारे साक्ष्य उपलब्द है। चुँकि अन्न अधिकोष की देखभाल समुदाय के हाथ में होता है इसलिए भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ इलाकों में अन्न कोषों का महत्व कम हो गया है, जैसे कि

(क) लोगों को आजकल सरकारी योजनाओं से – सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस), एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई. सी. डी. एस), से जरुरत के हिसाब से चावल और गेहुँ मिल जाता है।

(ख) वेतन आधारित कामों की वृद्धि से लोगों की आमदनी बढ़ी है, जिससे वे खुले बाजारों से अनाज खरीद सकते है।

(ग) अन्न अधिकोषों में केवल धान भंडारण होता है जबकि लोगों को अन्य खाद्यान्नों – दाल, खाद्य तेल, मसाले, कंदमूल आदि की भी जरुरत होती है।

रायगढ़ महाराष्ट्र की एक परिस्थिति (http://www.sas2.net/documents/Proceedings/Manjusha.pdf) इस पर प्रकाश डाल सकती है। पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्थानीय पंचायत समितीयाँ सशक्त और समंवित है वहाँ अन्न अधिकोषों का प्रबंधन सुचारु रुप से होता है। लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्न अधिकोषों में काफी विविधताएँ होनी चाहिए।

अन्न अधिकोषों के विभिन्न सफल प्रयासों की जानकारी हेतु दिल्ली के नजदीक स्थित 'नवदान्या' और 'जीन केम्पेन से संपर्क किया जा सकता है। अन्न अधिकोषों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए संलग्न सफल प्रयासों पर नजर डालें।

रामित बासु, यूनीसेफ, नयी दिल्ली

खाद्य असुरक्षा और ऊँची कुपोषण के समयकाल में यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। खाद्य और आजिविका सुरक्षा प्रोजेक्ट जो कि 'जीन केम्पेन' द्वारा झारखंड और बिहार में क्रियांवित किया गया था (जिसमें मैंने कार्य किया था), उसमें हम लोग केवल दो अन्न अधिकोष की स्थापना कर पाए थे – राँची और हजारीबाग में। राँची स्थित बिरसा कृषि विश्वविधालय का इसमें काफी सहयोग था।

यह प्रोजेक्ट एक समुदाय स्वामित्व रुपी उपक्रम था जिसमें गाँवों के निर्णय के अनुसार प्रयोजन में न आने वाले किसी भवन/ढ़ाँचा का उपयोग किया गया। हम लोग अन्न

अधिकोष की स्थापना के लिए जरुरती उपकरण मुहैया कराकर इसका नवीकरण कराते थे, जिसका कुल खर्च सत्तर हजार रुपए से ज्यादा नही था, वर्ष 2004-05 में।

मुद्दा है, "निरंतरता", और इसके लिए ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें ज्ञात होना चाहिए, पंचायती राज्य व्यवस्था के अतंर्गत अन्न अधिकोष के लिए प्रावधान है, जिसे कि अन्य कोषों के अलावा पंचायत को संभालना पड़ता है। इस अन्न अधिकोष पर पूरा ध्यान नही दिया गया है। हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अवस्था मालूम है। इस संर्दभ में इस कोष के जरिए ग्राम पंचायतों को अन्न अधिकोषों की स्थापना के लिए प्रोतसाहित करना, एक अच्छा विचार हो सकता है। ग्राम पंचायत की समाज कल्याण स्थायी समिती या सामान्य प्रशासन, इस कोष का प्रभारी बन सकता है। ग्राम पंचायत के प्रय़वेक्षण में स्वयं सहायता समूहों को भी इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

अन्न अधिकोषों का पुनरुत्थान देशी फसलों और फसल चक्रों पर आधारित होना चाहिए, जो कि स्थानीय समुदायों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है।

अगर हम इस जगह संमिलन (कोनभरजेंस) की बात करते है तो जहाँ एक जगह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, को फसलों की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है तो दूसरी ओर बी.आर.जी.एफ. से जरुरती सरंचना बनाई जा सकती है। समुदाय की भागीदारी, उधार ली गई अनाज की भरपाई और सदस्यों द्वारा निरंतर अनाज का योगदान आदि और इन सब का सख्ती से निर्वाह होना, अन्न अधिकोषों के सफल होने के लिए आवश्यक है।

अन्न अधिकोषों की स्थापना सही जगहों पर होनी चाहिए विषेशतः बाढ़ प्रवाहित इलाकों में, जिससे कि जरुरत मंदो को तत्काल राहत पहुँचाई जा सके।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत होगा और हमेशा खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए विषेश उपाय करेगा।

भवानी , एम.एस.एस.आर.एफ., चेन्नई *(प्रतिक्रिया 1)*

उड़ीसा और तमिलनाडू के आदिवासी इलाकों में सामुदायिक अनाज बैंकों की शुरुआत के दौरान, हमारा अनुभव यह रहा कि फसल विहीन समय अंतराल में क्षणिक भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए यह एक उपयोगी हस्तक्षेप है। यह हस्तक्षेप हालांकि एक स्वंयसंपूर्ण गतिविधि नहीं हो सकती। लेकिन विकेन्द्रीकृत भंडारण और खाद्यान के प्रबंधन एवम हस्तक्षेप की योजना की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय की आजिविका को सुरक्षित करना आवश्यक है। यह भूमि आधारित एवम गैर कृषि उद्यम गतिविधियों के एक मिश्र व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है। भूमि आधारित समर्थन से तात्पर्य है, किसानों के साथ काम कर, उन्हें पैदावार बढ़ाने हेतु कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस परिपेक्ष्य में अन्न अधिकोष के प्रबंधन में क्षमता का विकास और प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसके लिए भरपूर समय का निवेश होना चाहिए।

उचित भंडारण का प्रबंधन एक अन्य मुख्य पहलू है क्योंकि बहुत सारा अनाज अनुचित भंडारण की वजह से नष्ट हो जाता है। सरकार की अन्न अधिकोष योजना जो कि पहले जन जातिय कार्य मंत्रालय के अधीन था अब खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दायरे में है। फिर भी यह दूर्भाग्यवश भंडारण के लिए पर्याप्त आंवटन नहीं करता।

खाद्य और पोषण के सरकारी आवंटनों में पहुँच को सुलभ बनाना भी इस पूरे प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए।

हालांकि अन्न अधिकोष समिति में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है, पर सामान्यतः देखा गया है कि महिलाएँ इसके चालन और प्रबंधन में ज्यादा शामिल होती है।

स्थानीय बीजों के सरंक्षण और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से, जहाँ भी अनाज बैंक है, वहाँ हम लोगों ने 'बीज बैंक' भी स्थापित किया है। स्थानीय अनाजों जैसे कि 'मिलेट' (ज्वार, बाजारा आदि) और दालों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए इसके भंडारण को भी प्रोत्साहित किया गया है।

अन्न अधिकोषों का 'समुदाय स्वामित्व' इसकी निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि अन्य सदस्यों ने कहा है। क्या अन्न अधिकोषों के प्रबंधन में शामिल सदस्य समूहों के लिए कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए – जैसे वस्तु के रुप में भुगतान आदि? समुदाय में एकरुपता, सभी की पहुँच को सुनिश्चित करता है। ऐसे उदाहरण है जहाँ गाँव के लोगों ने स्वयं यह निर्णय लिया कि बेसहारा और जरुरतमंद, जो

ऋण चुकाने में असमर्थ है उनका कर्ज माफ कर दिया जाए।

आदर्श रुप में, क्षणिक भुखमरी को संबोधित करने के लिए अन्न अधिकोष की पहल - जागरुकता; प्रावधानों की पहुँच; स्थानीय अनाज, कंदमूल, सब्जी और फल आधारित समुदाय की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था आदि के जरिए समुदाय की पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की ओर अग्रसरित होना चाहिए।

सदस्य निम्नलिखित जानकारी से लाभांवित हो सकते है -

- देश भर में कई गैर सरकारी संगठन भुखमरी की समस्या के निराधरण के लिए अन्न अधिकोषों को बढ़ावा देने का काम कर रहे है – जैसे 'अग्रगामी', 'अनत्योदया', 'ग्राम विकास' – उडीसा, सी.ई.सी., डी.डी.एस. – आन्ध्रप्रदेश, ए.डी.एस. – महाराष्ट्र, ग्रामीण विकास ट्रस्ट – मध्यप्रदेश और राजस्थान।
- राष्टीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) हैद्राबाद ने, अनुभव के आदान-प्रदान के लिए 2007 में एक बैठक बुलाई थी।
- मध्यप्रदेश सरकार ने 2002 में एक 'अन्न कोष' योजना बनाई थी।

राज्य भर में अनाज बैंकों को बढ़ावा देने के लिए, एम.एस.एस.आर.एफ. ने अनुभव के आधार पर एक प्रशिक्षण पुस्तिका बनाई है और हम इसे आपके साथ बाटने में खुश होगें। वर्तमान में यह अंग्रेजी, उडिया और तमिल में उपलब्ध है।

भवानी , एम.एस.एस.आर.एफ., चैनेई *(प्रतिक्रिया 2)*

मैं निर्मला सुमनजी के विचारों से सहमत हूँ। वास्तव में विक्रेन्द्रीकृत तथा समुदाय प्रबंधित तंत्र जैसे कि अन्न अधिकोषो का लाभ यह है कि यह समुदाय की पारंपरिक रुप से पसंदीदा अनाजों का स्थानीय स्तर पर खरीद व भंडारण को प्रोत्साहित करता है। बीजों की सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए अन्न अधिकोषों के साथ साथ "बीज बैंक" भी वांछनीय है। समुदाय प्रबंधित खाद्य सुरक्षा तंत्र के संदर्भ में, "गुणसुत्र – बीज – अनाज" रुपी व्यवस्था, जैव विविधता संरक्षण व दीर्घकालीन निरंतरता काफी मददगार सिद्ध हो सकता है।

के. वी. पीटर, विश्व नोनी अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

जमीनी स्तर पर अनाज बैंक, ग्राहक केन्द्रित क्षेत्रों के अतंर्गत आने वाले राशन की दुकान की तरह है। वर्तमान में राशन की दुकान व्यापारी को निलाम की जाती है, जिनके पास

, चीनी, मिट्टी का तेल आदि रखने की समुचित जगह हो। राज्य सरकार के अधीन होने के कारण राशन वितरण उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। अनाज बैंको की परिकल्पना और इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है, अगर कुछ अच्छी तरह चलाई जा रही राज्यों (जैसे कि केरल), में राशन दुकानों के अध्ययन का प्रयास किया जाए।

अंजली त्रिपाठी, केथोलिक रिलीफ सर्विजेस (सी.आर.एस), लखनऊ

आदरणीय सदस्यों के अनुभवों को पढ़ने के बाद, मैं केथोलिक रिलीफ सर्विजेस (सी.आर.एस) के अन्न अधिकोष गतिविधियों, जो कि कार्यक्षेत्रों में समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, की जानकारी दे रही हुँ।

सी.आर.एस ने डी.एफ.आई.डी. समर्थित आर.आर.सी (वर्षा आधारित रबी फसल) कार्यक्रम क्रियांवित किया है। इस कार्यक्रम में बुदेलखंड क्षेत्र के किसानों को, चने की उन्नत प्राजाती बीज और धान की अगेती प्राजाती के बीज देकर सर्मथन दिया गया था। धान की ऐसी प्रजाती दी गई, जो कम पानी में चल सके और जिसे किसान सामान्य प्रजातीयों की अपेक्षा कम समय में ले सके। इस कार्यक्रम में समुदाय के लिए 'बीज बैंक' और 'अनाज बैंक' की परिकल्पना शुरु की गई थी। इससे किसानों को आगामी फसल चक्र में बीज की सुलभता हुई और साथ ही सूखे के समय खाद्यपूर्ति के लिए अनाज बैंक सहायक सिद्ध हुए।

ये बैंक किसान समुहों और स्वयं सहायता समुहों के सदस्यों द्वारा प्रबंधित व उनकी निगरानी में थे। यहाँ तक कि किसानों ने इन बैंकों द्वारा बचाए गए बीज को समुदाय के दूसरे किसानों को दिया जो की शुरुआत में इस कार्यक्रम के सदस्य नहीं थे। कार्यक्रम के परिकल्पना को विस्तारित करने के लिए यह एक और तरीका था। यह कार्यक्रम कुछ मुठ्ठी भर किसानों से शूरु हुआ था जो कि बढकर 8000 किसान (कार्यक्रम से लाभांवित हुए) तक पहुँच गया। यह समुदाय के कुछ सदस्यों की घरेलू आय वृद्धि में भी सहायक हुआ है, यद्यापि इसे अभूतपूर्व वृद्धि का दावा नहीं किया जा सकता। साथ ही इस कार्यक्रम ने कुछ किसानों को पलायन करने से भी बचाया है।

यहाँ मैं यह दोहराना चाहूँगी कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह एक बड़ा कदम नहीं है फिर भी कार्यक्रम ने यह सीख दिया कि जो तकनीक/पद्धति/परिकल्पना स्थानीय

समुदाय के जरुरतों का सहायक बनें, वह बहुत अच्छा प्रतिफल देता है।

निर्मला सुमन, यूनीसेफ, लखनऊ

अन्न अधिकोष की अवधारणा पर काम करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय फसलों की बहुत सारी प्रजातियाँ है जो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। इन फसलों का पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भुमिका है और ये स्थानीय जरुरतों को पूरा कर वर्ष-भर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होते है। ऐसा ही एक फसल है मड़ुआ (एक किस्म का मिलेट) जो कि बिहार के मधुबनी इलाके में उगाया जाता है। 2007 में क्षेत्र का दौरा करते समय मैंने पाया कि इस फसल के दोहरे फायदे है। पहला तो यह कि यह काफी पोषक है, इसे उगाने में बहुत कम पानी की अवश्यकता होती है जिससे असिंचित भुमि में भी इसे उगाया जा सकता है, तथा फसल कटने के बाद अवशेष को खेत में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है जो कि जैव उर्वरक की तरह काम करता है। जून के महीने में किसान मड़ुवा काटकर धान की रुपाई करते है, जिसका अच्छा फसल होता है। स्थानीय किसानों के अनुसार मड़ुवे के बाद धान की फसल लगाने से अच्छी पैदावार मिलती है।

लेकिन बहुत सारे किसान मड़ुवे को छोड़कर नगदी फसलों जैसे कि सब्जीयाँ, के तरफ बदल रहे हैं। इन फसलों को ज्यादा पानी, खाद और कीटनाशकों की जरुरत होती है – कारण की ज्यादा माँग वाली सब्जीयाँ अधिकतर संकर किस्म की होती है। इसलिए जब बाढ़ के दौरान फसलें नष्ट होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी नगदी फसलों के लिए बहुत लोग ऊँची दरों पर कर्जा लेते है और इसलिए आपदा के समय बरबादी से नहीं बच सकते।

इन अनुभवों ने लोगों को स्थायी/निरंतर कृषि के प्रति अधिक जागरुक किया है। ऐसी फसलों को अन्न अधिकोष के फसलों में शामिल करना चाहिए।

नीरा रामाचन्द्रन, स्वतंत्र परामर्शदाता, नई दिल्ली

अन्न अधिकोष परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ उदाहरण/अनुभव आपके उपयोगी हो सकते है –

सामुगदायिक अन्न अधिकोष प्रबंधन के अनुभव – बुरकिना फासो पश्चिमी अफ्रीका

http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+31-40/Footsteps+32/Community+Grain+Banks.htm

अन्न अधिकोष प्रबंधन का प्रशिक्षण पाठ्क्रम
http://www.ilo.org/dyn/empent/docs/F1734331776/grain%20banks%20text.pdf

भारत में व्यवहार होने वालें कम लागत के भंडारण व्यवस्था
http://www.fao.org/wairdocs/x5002e/X5002e02.htm

दिलनवाज़ महंनती, आई.एल.ओ, नई दिल्ली

मैं एम.पी.आर.एल.पी. परियोजना का अभिनंदन करना चाहूँगा जो कि अन्न अधिकोष द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, समुदाय को संगठित कर परिणाम स्वरुप सशक्तिकरण करने तथा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी से लड़ने का यह साकारात्मक कदम उठाया है।

इस संदर्भ में अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में आई.एल.ओ. के एकोपाम परियोजना का उदाहरण काफी जानकारी देता है। अन्न अधिकोष का प्रबंधन – 'अंदरूणी संगठन' नामक मोडयूल, चार मोडयूलों के श्रृखंला में एक है, जिससे बाकी – लाजिस्टीक, एकाउंटेंसी और सीजन स्टेटमेंट है। इस बारे में अधिक जानकारी आई.एल.ओ. की सहकारी शाखा से उपलब्ध हो सकता है - (COOP@ilo.org). यह गौर करने योग्य है कि इनका स्थानीय स्थिती और जरुरत के मुताबिक उपयुक्त अनुकुलन होना चाहिए।

कुछ स्थानीय उदाहरणों में, अग्रगामी – उड़ीसा में आदिवासियों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की ओर कार्य करता गैर सरकारी संस्था, जिसका समुदाय प्रबंधित अन्न अधिकोषों पर कार्य काफी उल्लेखनीय है। इस संस्था ने उड़ीसा में रायगढ़ जिले के काशीपूर ब्लाक तथा कोरापूट जिले के दशमंतपूर ब्लाक में 700 अन्न अधिकोषों की स्थापना की है जिसमें 500 अन्न अधिकोष प्रत्यक्ष रूप से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। संपर्क के लिए उनका वेबसाइट है www.agragamee.org

---

राधा गोपालन, ऋषि वैली स्कूल, मदनपल्ली, चित्तुर, आन्ध्रप्रदेश

चुँकि अन्न अधिकोषों की स्थापना का उद्धेश्य सुरक्षा के मसले को संबोधित करना है, इसलिए स्थानीय परंपरागत फसलों जैसे मिलेट, दहलन आदि को अन्न अधिकोष का अभिन्न अंग होना चाहिए। हम लोग आन्ध्रप्रदेश में चित्तुर जिले के कुछ गाँवों में स्थानीय समुदायों के साथ काम कर रहे है और हमने पाया कि मिलेट और दलहनी फसलों की

प्रजातियाँ, जो कि सफेद चावल (पालिश की हुई) की अपेक्षा काफी पौष्टिक है, को खाद्य पद्धति से निकाल दिया गया है। गाँव के बुजुर्गों से बातचीत करने पर पता चला कि बहुत सारी परियोजनाओं जैसे कि सस्ता चावल वितरण और नगदी फसलों की बढ़ती माँग के कारण आज के पीढ़ी के किसान मिलेट तथा दलहनी फसलों को नहीं उगाना चाहते है। जैसा कि आप सभी को मालूम है इससे महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों (प्रोटीन, खनिज तत्व आदि) का नुकसान होता है और यह भूमि की उर्वरता, पानी के साथ साथ स्थानीय लोगों के स्वास्थय के साथ भी एक समझौता है।

फसलों की विभिन्नता के ह्रास से, स्थानीय बीजों का कृषि पर्यावरण तंत्र से विलुप्त होना, इसका एक और पहलू है।

इसलिए यह आवश्यक है कि अन्न अधिकोषों द्वारा खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ-साथ, स्थानीय अनाज के प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए “बीज बैंक” को भी जोडा जाए।

अल्का पांडे, द इंडियन एक्सप्रेस, लखनऊ

उत्तरप्रदेश के सुखा ग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्न अधिकोष के सफल उदाहरण मौजूद है। पिछले छः सालों से परमार्थ समाज सेवी संगठन नामक संस्था उराई जिले में पचास अन्न अधिकोष चला रहा है।

इन अन्न अधिकोषों के स्थापना का उद्देश्य गाँव के लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था। उराई जिले के माधोगढ़, रामपूरा और नांदीगाँव में ये अन्न अधिकोष संपूर्णतः समुदाय के भागीदारी से चल रहा है। अधिकोष को बनाने के लिए हर एक परिवार को दान स्वरुप अनाज देने को कहा जाता है। जब अनाज जमा हो जता है तो संस्था भी इसमें अनुकूल योगदान करता है, जो कभी समान अनुपात में होता है या अधिक। गाँव की समिति गठित की जाती है, जिसमें विषेशकर महिलाएँ सदस्य होती हैं। समिति नियमित रूप से बैठक करती है और समीक्षा कर लाभार्थियों का चयन करती है – जो गरीबों मे एकदम गरीब होते है।

दिलचस्प बात यह है कि लाभार्थियों से कोई पैसा नहीं वसुला जाता, वरण उन्हे अनाज के रूप में ही इसे लौटाना पड़ता है – मूल मात्रा के अलावा इसका चौथाई हिस्सा।

अगर लाभार्थी लिए गए अनाज को लौटाने में असमर्थ होता है तो अन्य लोग इसका भरपाई करते है।

इस संस्थान के निर्देशक – श्री अनिल सिहंजी को निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है। ई मेल - parmarthorai@sancharnet.in ; मोबाईल – 919415064472

अरद्वेन्दू एस. चटर्जी, डी.आर.एस.सी., कोलकाता

बहुत लोगों द्वारा मिलेट, दलहन आदि फसलों को छोड देने के पीछे कारण है सस्ते चावल की आपूर्ति। मिलेट का समर्थन मूल्य न होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय अनाजों का समावेश न होना आदि इसके कुछ और कारण है। डेकेन डेवलपमेंट संस्थान ने आंध्रप्रदेश के मेडक जिले में पतनचेरू के पास मिलेट उगाने के लिए प्रोतसाहित किया है (http://www.grain.org/g/?id=134)।

सरकारी संस्थाएँ अक्सर अंतराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के राशी द्वारा, पानी और आदान सघन नगदी फसलों को बढ़ावा देते है। व्यापारी भी तंबाकू, कपास आदि फसलों को बढ़ावा देते है।

हमारी संस्था खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा परियोजना के तहत अन्न अधिकोषों को स्थानीय एवम निरंतर कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के हिस्से के तौर पर बढ़ावा दे रहा है।

पश्चिम बंगाल में मुख्य अनाज है – धान। हम लोगों ने बहुत सारे अन्न अधिकोषों को एक परिक्रामी निधि से प्रारंभिक कोष (अनाज के रूप में) देकर शुरू किया है। भंडार गृह साधारणतः पुआल की रस्सी से बनाया जाता है। इन भंडार गृहों का तल पत्थर या कंक्रीट से बनाया जाए ताकी चुहों द्वारा नुकसान न हो इसके लिए हम लोग समुदाय को प्रोत्साहित करते है ।

हम लोगों ने पाया कि थोड़ा प्रशिक्षण और सामयिक सलाह-मशवरा से गरीब समुदाय सफलता पूर्वक अन्न अधिकोष चला सकते है। अगर वे अनाज स्थानीय महजनों से उधार लेते है तो वे ऋण का मूलधन भी चुका सकते है और काफी बचत कर, ब्याज की रकम भी चुका सकते है।

बंगाल के सूखे क्षेत्रों में, हमने ज्वार, मकई, बाजरा के साथ अरहर, तिल, बरबटी, उरद आदि फसलों का मिश्रित फसल चक्र को बढ़ावा दिया है।

जहाँ पर किसानों का समूह बनाया है वहाँ बारीश के पानी को रोकने की व्यवस्था की गई (कभी कभी 'नरेगा' की राशी द्वारा) जिसका काफी बढ़िया परिणाम हुआ है।

खाद्य सुरक्षा के लिए घर के पिछले आँगन में कंद-मूल फसल उगाकर, जीवित खाद्य बैंक की स्थापना एक और विकल्प हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए डी.आर.एस.सी. का वेबसाइट देखा जा सकता है । प्रशिक्षण के लिए इस संस्थान के सचिव को लिखे।

आशा है यह जानकारी आपके काम आयेगी।

अच्युत दास, अग्रगामी, काशीपूर, उड़ीसा

सामुदायिक अन्न अधिकोषों का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद। सदस्यों द्वारा रखी गई राय काफी रोचक है यद्यपि काफी जमीनी अनुभव आना बाकी है।

समुदाय अन्नकोष कोई शैक्षण प्रसताव नही है। एम.एस.एस.आर.एफ. के भावानीजी ने एक पुस्तक के बारे में कहा है जिसमें 'अग्रगामी' के कार्यो के बारे में उल्लेख है।

हम लोगों ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक अन्न अधिकोषों पर काफी काम किया। और बहुत सारे गैर सरकारी संस्थाओं ने हमारे द्वारा दर्शाये गए मॉडलों को विस्तार करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में आईफेड समर्थित आदिवासी विकास योजना ने भी सामुदयिक अन्न अधिकोषों की स्थापना का प्रयास किया है। हमारे दृष्टिकोण की और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेभसाईट देखें - www.agragamee.org/g**bank**.htm. हम लोगों को ठीक से मालूम है कि क्यों और कैसे एक सामुदायिक अन्न अधिकोष विफल हो जाता है। हम प्रभावशाली रुप से यह कह सकते है कि अगर आदिवासी क्षेत्रों में सामुदयिक अन्न अधिकोष का सफल प्रबंधन हो तो जून से सितम्बर के महीने तक (जिस समय खेतों में फसल नही होता) भूखमरी और कुपोषण से लड़ा जा सकता है।

आदिवासी क्षेत्रों में भुखमरी और कुपोषण से मृत्यु के कारण 2001 में आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने एक लाख आदिवासी गांवों में सामुदायिक अन्न अधिकोष की स्थापना का

महत्वकाक्षी योजना बनाया था। देश के स्तर पर कुछ चर्चायें भी हुई थी। आई.एल.ओ. ने कार्यशाला भी आयोजित की थी। सामुदायिक अन्न अधिकोषों के सरकारी परिकल्पना की अगर समलोचना की जाए तो – कार्यस्तर का आकार, उपरी तह से नीचे की ओर जाने वाली वितरण प्रणाली, स्थायीत्व व निरंतरता आदि का परीक्षण आवश्यक है। मैं यहाँ तक कह सकता हुँ कि सामुदायिक अन्न अधिकोषों की सफलता समुदाय की स्वयं स्थायीत्व व स्वयं प्रबंधन निष्ठा पर निर्भर करता है। यह एक आश्चर्यजनक घटना होगी अगर गाँवों में ट्रक में भरकर 100% छूठ पर चावल लाए जाए, स्थायी व सफल अन्न अधिकोष कृत्रिम रूप से बनाए जा सके। अगर देश में इस तरह की कोई सरकार समर्थित सामुदायिक अन्न अधिकोष सफलता पूर्वक चल रही है, तो उनका अध्ययन होना चाहिए और उनको विस्तार करने योग्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

मै यह मानता हूँ कि हमारे सामुदायिक अन्न अधिकोष सौ प्रतिशत सफल नही है। अमेरिका के कारनेल विश्वविधालय के डा.रूचिरा भठमिश्रा ने हमारे सामुदायिक अन्न अधिकोषों पर विस्तृत शोद्य किया है और सूदुर आदिवासी क्षेत्रों में खाध व पोषण सुरक्षा के परिपेक्ष्य में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें यह चर्चा भेज रहा हूँ ताकि वो भी इस पर अपने विचार भेज सके। सामुदायिक अन्न अधिकोष का प्रतिफल इतना शक्तिशाली होता है कि यह महाजनों को काफी प्रभावित करता है। अततः इससे अन्न अधिकोष को तोडने के लिए गांव के शक्तिशाली बलों द्वारा एक दुष्ट चाल पनपता है। अगर पर्याप्त जागरूकता व प्रबंधन कार्यक्षमता न हो तो विपरीत शक्तियाँ अन्न अधिकोष को तोड़ने में सफल हो जाती है।

भंडारण एक बड़ी समस्या है। कम लागत वाली भंड़ारण तकनीकों को आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत तकनीकों के और अधिक विकास के लिए प्रयास आवश्यक है।

हैद्राबाद स्थित अनाज भंडारण शोध संस्थान ने काफी मॉडलों और इनके क्रियांवन का विकास किया है।

अनाज ऋण का माध्यम, एक जटिल प्रबंधन व्यवस्था है और हमारे स्वयं सहायता समुह इसे संभालने में सक्षम नही हो सकते है। बारंबार सूखा व बाढ़ से फसल की बरबादी, तेजी से पैदावार में गिरावट आदि भी अन्न अधिकोषों की सफलता और विफलता का एक और मुख्य कारण है अनाजों की किस्में। आदिवासी लोग स्थानीय मिलेटस जैसे मडुआ, फोक्सटेल मिलेट को ज्यादा पसंद करते है और धान/मक्का आदि को कम प्रधानता देते है, जिनका भंडारण काफी मुश्किल होत है।

सफलता और विफलता के कारणों से सीख लेकर सामुदायिक अन्न अधिकोषों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार अग्रगामी और एम.एस.एस.आर.एफ, पंचायत स्तर पर अन्न अधिकोष की योजना बना रहे थे। इस सोच के तहत पूरे पंचायत के समुदायों के लिए एक बृहत सामुदायिक अन्न अधिकोष बनाने की कल्पना की गई जिसमे वर्ष भर लेन देन हो। स्वंय सहायता समूहों के फेडरेशन के तरह, हम लोगों ने पूरे पंचायत के लिए व्यवस्था बनाने की परिकल्पना की थी। भावानीजी इस पर कुछ और प्रकाश डाल सकती है। लेकिन यह प्रयासयोग्य है।

हम लोगों का मानना है कि आदिवासी इलाकों में, स्व-स्थायी-एवम सर्वागिंक विकास के लिए सामुदायिक अन्न अधिकोष एक पहला कदम है। यदि एक गाँव अन्न अधिकोष को स्थायी व निरंतर कर सकता है तो वह केसी अन्य विकास के पहल को भी स्थायी व निरंतर कर सकेगा। यह हमारे अनुभवों का नेचोड है।

इसे सशक्त करने के लिए समुदाय, पंचायत, गैर सरकारी संस्थाओ, सरकारी एजंसीयों, अंतराष्टीय गैर सरकारी संस्थाऑ और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाऑ जैसे युनिसेफ, आई.एल.ओ., यू.एन.डी.पी. आदि में एक सहयोगी रूपरेखा की आवश्यकता है। उड़ीसा के कोरापूट एवम कालाहांडी जिले में नब्बे के दशक में, युनिसेफ द्वारा भुखमरी रोकने के लिए घरेलू खाध सुरक्षा परियोजना इस संबंध में एक दिशा निर्देशक है।

अगर कोई प्रशन या स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो आप मुझे लिख सकते है।

रूचिरा भट्मिश्रा, कोर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका

मैं अग्रगामी के श्री अच्युत दास जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होनें मुझे सोल्यूशन एक्सचेंज के इस चर्चा में सम्मिलित किया। श्री उत्पल मैत्रा के द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर के रूप में, मैं उड़ीसा के रायगढ़ और कोरापूट जिले में अन्नकोषों पर किये गए मेरे शोध का निष्कर्ष प्रस्तुत कर रही हुँ। इन इलाकों में अग्रगामी अन्नकोषों के स्थापना और इसके समर्थन के लिए पिछले 20 साल से सक्रिय है। यह समझने के लिए कि लिए कि वह कौन से कारण है जिनसे पता लगे कि अन्नकोष कार्यशील है या नही? मैंने कोरापूट जिले में अन्नकोष तथा गाँव के स्तर पर चालू और बंद हुए अन्नकोषों के तथ्यों का अध्ययन किया।

अन्नकोष कार्यशील होगें या नही, या कब तक कार्यशील रहेगें, यह निर्धारित करने के लिए मैंने पाया कि अन्नकोषों की अपेक्षा गाँव के स्तर के कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो यह सूचित करता है कि स्थिरता और निरंतरता के लिए क्षेत्र का चयन कितना प्रमुख है।

अन्न अधिकोषों के प्रभाव, के साक्ष्य के रूप में रायगढ़ में किए गए शोध में मैनें पाया कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार पर अन्न अधिकोषों का कोई खास प्रभाव नही हुआ, लेकिन महाजनों से उधार लेने कि संख्या जरूर कम हुई। इस तरह यह लगता है कि अन्न अधिकोष ऋण सेवा उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। जाँचे गए स्वास्थ्य सूचकों के परिणामों पर प्रभाव न होना यह इंगित करता है कि – एक प्रभावी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा के विभिन्न प्रक्रियाओं को समझना काफी महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा एक बहु आयामी मुद्दा है और संकट के समय ऋण आवंटन के लिए मात्र अन्न अधिकोषों की स्थापना प्रभावशाली नहीं हो सकती, अगर स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता आदि पूरक कार्यक्रम नही आरंभ किये जाए।

मैं आँकडों की उपलब्धता न होने के कारण अन्न अधिकोषों का ‘लागत लाभ’ विश्लेषण नहीं कर सकी। लेकिन लाभकारी प्रभाव होने के बावजूद कोई कार्यक्रम कार्यावयन के योग्य है या नहीं, जानने के लिए लागत प्रभावशीलता एक महत्वपूर्ण सूचक है। अन्न अधिकोष समुदाय के सदस्यों के बीच होने के कारण, परिवहन लागत या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी। लेकिन भंडारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि श्री अच्युत दास जी ने उल्लेख किया है, मैनें गाँवों के सर्वेक्षण के दौरान पाया कि प्रभावी भंडारण का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता था।

इसके अलावा केन्द्रीकृत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की अपेक्षा चुँकि सामुदायिक अन्न अधिकोषों का प्रबंधंन स्थानीय स्तर पर होता है, इसलिए खाधान्न-कमी की जरूरतों को ज्यादा तेजी से पूरा किया जा सकता है। यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण होता है। पर अन्न अधिकोषों के स्थिरता और निरंतरता में सूखा एक मुख्य समस्या है। सूखाग्रस्त इलाकों में अन्न अधिकोष की संरचना निर्धारित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि सूखे के वर्षों के बाद अनाज भंडार को कैसे भरा जाए।

यद्यपि जमीनी स्तर की अनुभव, प्रभावी अन्न अधिकोष की योजना बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं श्री उत्पल मैत्रा और अन्य लोग जो कि मध्यम और बड़े

स्तर पर अन्न अधिकोष कार्यांवयन के योजना मे जुड़े है, को बताना चाहूँगी कि उन्हें शूरूआत से शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे योजना शुरू करने प्रारंभ में ही तथ्य इकट्ठा की जा सकेगी जो कि योजना की सफलता में समुदाय की परिस्थिती का संदर्भ स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के प्रभाव का मजबूत आकलन करने में भी यह काफी आवश्यक है जो कि न केवल भारत के खाद्य सुरक्षा से संबंधित लोगों के बीच इन मुद्दों का ध्यान आकर्षण करेगा वरण, विश्व खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। यह साक्ष्य आधारित वाद-विवाद को भी समर्थन देगा – कि क्या हो सकता है और क्या नहीं – जिससे भविष्य में प्रभावशाली – कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सके।

सूरेष पटेल, कर्मदक्ष, बिलासपूर

ग्राम पंचायत बतरा पाली ब्लाक से 14 किलोमीटर एवं कोरबा जिले से 85 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इस पंचायत के 20 मुहल्ले राजस्व गाँव बतरा के अंतर्गत आता है। यह पंचायत लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

इस गाँव में स्थित ग्रेन बैंक की योजना सरकार की है। यह योजना (दिनांक 01/06/2006 से ब्लाक द्वारा) 'महिला समूह' के गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले आदिवासी परिवारों के लिए प्रदान की गई थी। ब्लाक अधिकारियों ने कहा कि यह योजना सिर्फ 40 परिवारों के लिए है। यहाँ कर्मदक्ष संस्था के सहयोग से 'क्लस्टर' के माध्यम से 13 समूह से 40 महिलाओं का समूह बनाकर ब्लाक से चावल लिया गया। फिर इस चावल को क्लस्टर में मिटिग कर 13 समूहों के सदस्य अपनी सदस्य की आवश्यकता अनुसार बाँट लिया।

इस ग्रेन बैंक के शुरूवात के समय निम्नलिखित नियम बनाए गए -

1. इस समिति में तीन पदाधिकारी चुना गया – अध्यक्ष, कोशाध्यक्ष, व सचिव।
2. ब्याज – 100 किलोग्राम में 10 किलो वार्षिक, तय किया गया।
3. चावल वापसी करते समय साफ चावल लाना पड़ेगा।
4. ब्याज प्रति माह जमा करना पड़ेगा।

5. चावल की आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सदस्य अपने समूह के माध्यम से क्लस्टर को आवेदन देगा।

बतरा पंचायत में 22 महिला समूह बने हुए है। इस ग्रेन बैंक को प्रारंभ में 13 समूहों के 195 महिलाओं ने 40 क्विंटल चावल से शुरू किया था। अब 16 समूहों के 227 महिलायें इससे फायदा ले रहें है। वर्तमान में भंडार में 46.37 किलो चावल है।

इस ग्रेन बैंक की बैठक प्रति माह 25 तारिख तय किया गया है - इसी दिन लेन देन एवं चर्चा किया जाता है। क्लस्टर के माध्यम से चावल रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता है इसके लिए समूह के महिलाओं ने क्षेत्रिय विधायक एवं गृहमंत्री से बातचीत किया और साथ ही साथ कलेक्टर साहब एवं ब्लाक सी.ई.ओ. से भी निवेदन किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके लिए पंचायत से घर बनवाने के लिए जमीन 03 डिसमिल जरूर मिल गया है।

घर बनवाने के लिए समूह अपने स्तर पर प्रति सदस्य 100 रूपये जमा करने का निर्णय क्लस्टर मे लिया गया। एवं वर्तमान में 4900 रूपये ही जमा हो पाया है।

क्र.	समुह का नाम	मुहल्ला का नाम	कुल सदस्य	आदिवासी	अन्य
01	अन्नपूर्णा	बतरा	17	17	00
02	दुर्गा	बतरा	12	12	00
03	नयाअंजोर	आवासपारा	11	11	00
04	पूर्णिमा	ढोडीपारा	15	15	00
05	सरस्वती	ढोडीपारा	14	14	00
06	गोडवाना	मुडाभाठा	15	15	00
07	महालक्ष्मी	झोरकीपारा	13	11	02
08	शंकर	कुम्हीपानी	13	00	13
09	राम	कुम्हीपानी	14	06	08
10	बजरंग	कुम्हीपानी	19	00	19
11	मां संतोषी	नगराही	12	12	00
12	लखनी देवी	भदरापारा	20	18	02
13	जागृति	भदरापारा	20	04	16
14	राखी सहेली	लहरापारा	10	08	02

15	विकास	लहरापारा	10	09	01
16	कल्याणी	ढोडीपारा	12	10	02
कुल			227	162	65

Many thanks to all who contributed to this query!

If you have further information to share on this topic, please send it to Solution Exchange for the Food and Nutrition Security Community in India at se-food@solutionexchange-un.net.in with the subject heading "Re: [se-food] प्रशन: 'समुदाय चलित व प्रबंधित अन्न अधिकोषों का विकास – अनुभव - Additional Reply."

Disclaimer: *In posting messages or incorporating these messages into synthesized responses, the UN accepts no responsibility for their veracity or authenticity. Members intending to use or transmit the information contained in these messages should be aware that they are relying on their own judgment.*

Copyrighted under Creative Commons License "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5". Re-users of this material must cite as their source Solution Exchange as well as the item's recommender, if relevant, and must share any derivative work with the Solution Exchange Community.

Solution Exchange is a UN initiative for development practitioners in India. For more information please visit www.solutionexchange-un.net.in

---